विचार कर सकते हैं। क्या इस तरह का सुझाव आया और इस संदर्भ में सरकार की क्या सोच है ?

SHRI EDUARDO FALEIRO : Sir, there are suggestions and counter-suggestions, but the basic point, as I have said, is that whenever these suggestions come, we look into them within the framework of what I have said. It has to be acceptable, acceptable to this Parliament, acceptable to this country. There are innumberable suggestions and counter-suggestions from different sources in this regard.

श्री राम नरेश यादव : महोदय, यह इस संबंध में कई बार प्रधान मंत्री जी से भी इस विवाद के संबंध में बातचीत हुई और उस संबंध में बहुत कुछ बातें भी आईं । मैं केवल एक बात जानना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार जो सीमा-विवाद के संबंध में बात-चीत अब तक हुई है उस से क्या प्रधान मंत्री जी सन्तुष्ट हैं कि सचमच में इस वार्ता का लाभ आगे भी अच्छा मिलेगा और क्या उससे वातावरण अति सुन्दर बनेगा ?

SHRI EDUARDO FALEIRO : Sir, the hon. Member will know that the nature of this border and the location of this border is not a simple one and it is an extremely inaccessible area and, therefore, Sir, it is not an easy task to demarcate the border. Therefore, these talks are going on and I have indicated the direction of these talks and I have also indicated that there is a consensus of policy on how to proceed with this matter.

उर्वरकों का उत्पादन

*44. **श्री शिवचरण सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न उर्वरकों की राज्यवार आवश्यकता कितनी-कितनी है;

(ख) देश में किन-किन विभिन्न उर्वरकों का उत्पादन होता है और कितनी-कितनी मात्रा में होता है;

(ग) विदेशों से कितनी मात्रा में उर्वरकों का आयात किया जाता है और उन पर कितनी धनराशि खर्च की जाती है; और

(घ) उर्वरकों के उत्पादन में देश के कब तक आत्म-निर्भर बन जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिंता मोहन) : (क) से (च) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) खरीफ 1992 और रबी 1992-93 के दौरान विभिन्न उर्वरक न्यूट्रिसन्ट्स (अर्थात् नाइट्रोजन) (एन), फास्फेट (पी) और पोटाश (के) की राज्यवार अनुमानित आवश्यकता संलग्न अनुबन्ध सं. 1 और 2 में दी गयी है । **(नीचे देखिए)**

(ख) देश में उत्पादित विभिन्न मुख्य उर्वरकों सहित अप्रैल-अक्तूबर, 1992 के दौरान उत्पादित मात्रा नीचे दी गयी है :—

(000 मी. टन)

उत्पाद का नाम	उत्पादन
यूरिया	7340·3
अमोनियम सल्फेट	303·2
कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट	251·9
अमोनियम क्लोराइड	69·0
डी ए पी	1685·8
एस एस पी	1399·4
एनपी/एनपीके	
20·7 : 20·7	174·4
15·15:15	233·6
17:17:17	441·4
10:26:26	170·1
12:32:16	142·6
14:35:14	20·8
19:19:19	99·4
14:28:14	00·8
28 : 28	216·5
16 : 20	59·7
23:23	156·8
20:20	398·8
योग :	13163·1

(ग) 1992-93 (अक्तूबर, 1992 तक) के दौरान विदेश से आयातित उर्वरकों की मात्रा तथा उन पर व्यय धन राशि नीचे दी गयी है :—

(मात्रा लाख टनों में)
(लागत भाड़ा मूल्य रु० करोड़ों में)

सामग्री	(अक्तूबर 92 तक)*	
	मात्रा	लागत भाड़ा मूल्य
यूरिया	12.69	523.73
म्यूरिएट आफ पोटाश	16.34	612.44
सल्फेट आफ पोटाश	—	—
डी ए पी	14.27	706.50
एन पी के	1.30	70.75
योग		1913.42

*आंकड़ों में मात्र सरणीबद्ध अभिकरण (एम एम टी सी) के माध्यम से सरकार द्वारा आयात की गयी उर्वरकों की मात्रा सम्मिलित है।

(घ) भविष्य के लिए सरकार का उद्देश्य नाइट्रोजनी उर्वरकों के उत्पादन में अधिकतम आत्म निर्भरता प्राप्त करना है। जबकि नाइट्रोजन के मामले में यह अनुमान लगाया जाता है कि आठवीं योजना के दौरान मांग का 90 प्रतिशत स्वदेशी उत्पादन के माध्यम से पूरा किया जायेगा, फास्फेट के मामले में घरेलू कच्चे मालों की कमी उत्पादन में आत्म निर्भरता नहीं आने देगी किन्तु लक्ष्य स्वदेशी अवस्कों का उपयोग बढ़ाना है। जहां तक पोटाश का संबंध है सम्पूर्ण मांग आयातों के जरिये पूरी की जाती है क्योंकि देश में पोटाश के ज्ञात स्रोत नहीं हैं।

अनुबन्ध-1

खरीफ 1992 के लिए अनुमानित आवश्यकता

(000 टन में)

राज्य	एन	पी	के	एन+पी+के
आंध्र प्रदेश	522.20	291.05	69.29	882.54
कर्नाटक	275.88	207.50	105.00	588.38
केरल	52.37	34.47	66.16	153.00
पांडिचेरी	5.20	2.49	3.40	11.09
तमिलनाडु	175.12	86.32	117.10	378.54
अंडमान और निकोबार	0.25	0.21	0.25	0.71
योग (दक्षिणी क्षेत्र) :	1031.02	622.04	361.20	2014.26

राज्य	एन	पी	के	एन+पी+के
गुजरात	217.15	115.37	32.27	364.79
मध्य प्रदेश	298.15	185.45	33.35	516.95
महाराष्ट्र	499.40	228.80	129.50	857.70
राजस्थान	136.02	82.92	5.70	224.64
गोआ	2.51	1.78	1.58	5.87
दमन और दीव	0.12	0.06	0.02	0.20
दादर और नगर हवेली	0.52	0.36	0.05	0.93
योग पश्चिमी क्षेत्र :	1153.87	614.74	202.47	1971.08
हरियाणा	202.94	46.99	2.50	252.43
पंजाब	404.28	90.88	15.00	510.16
उत्तर प्रदेश	705.06	154.86	48.60	908.52
हिमाचल प्रदेश	16.97	3.15	2.48	22.60
जम्मू और कश्मीर	27.46	9.48	3.81	40.75
दिल्ली	3.78	0.87	0.18	4.83
चंडीगढ़	0.14	0.02	0.01	0.17
योग उत्तर क्षेत्र :	1360.63	306.25	72.58	1739.46
बिहार	235.66	54.36	19.28	309.30
उड़ीसा	90.72	27.03	14.08	131.83
पं० बंगाल	149.39	91.91	69.55	310.85
योग पूर्वी क्षेत्र :	475.77	173.30	102.91	751.98
आसाम	13.62	8.74	8.63	30.99
त्रिपुरा	3.09	1.28	1.19	5.56
मणिपुर	7.70	3.33	0.60	11.63
मेघालय	1.00	0.68	0.17	1.85
नागालैण्ड	0.28	0.16	0.11	0.55
अरुणाचल प्रदेश	0.15	0.06	0.10	0.31
सिक्किम	0.83	0.37	0.24	1.44
मिजोरम	0.20	0.29	0.09	0.58
टी बोर्ड (उ० पू०)	12.88	2.83	15.00	30.71
योग उत्तर पूर्व क्षेत्र :	39.75	17.74	26.13	83.62
सम्पूर्ण भारत :	4061.04	1734.07	765.29	6560.40

अनुबन्ध-2

रबी 1992-93 के लिए अनुमानित आवश्यकता

(000 टनों में)

राज्य	एन	पी	के	एन+पी+के
आंध्र प्रदेश	603.93	214.39	73.00	**891.32**
कर्नाटक	212.09	115.69	75.00	**402.78**
केरल	43.46	24.30	39.60	**107.36**
पांडिचेरी	7.55	2.88	4.25	**14.68**
तमिलनाडु	298.64	106.90	152.08	**557.62**
अंडमान और निकोबार	0.09	0.06		**0.15**
योग दक्षिण क्षेत्र :	1165.76	464.22	343.93	**973.91**
गुजरात	262.78	120.96	34.01	**417.75**
मध्य प्रदेश	264.56	176.50	23.50	**464.56**
महाराष्ट्र	311.69	174.63	96.80	**683.12**
राजस्थान	209.61	98.19	5.52	**313.32**
गोआ	1.72	1.25	1.00	**3.97**
दमन और दीव	0.38	0.28	0.12	**0.78**
दादर और नगर हवेली	0.15	0.12	0.08	**0.35**
योग पश्चिम क्षेत्र :	1050.89	571.93	161.03	**1783.85**
हरियाणा	302.11	128.06	3.98	**434.15**
पंजाब	592.89	272.73	8.68	**875.30**
उत्तर प्रदेश	1084.80	361.79	81.92	**1528.51**
हिमाचल प्रदेश	14.78	4.35	3.59	**22.72**
जम्मू और कश्मीर	14.23	6.99	1.20	**22.42**
दिल्ली	8.05	2.04	0.30	**10.39**
चंडीगढ़	0.22	0.11	0.03	**0.36**
योग उत्तर क्षेत्र :	2017.08	777.07	99.70	**2893.85**
बिहार	274.15	103.60	39.04	**416.79**
उड़ीसा	61.53	27.46	17 63	**106.62**
पं० बंगाल	300.53	154.88	110.40	**565.81**
योग पूर्वी क्षेत्र :	636.21	285.94	167.07	**1089.22**

(000 टनों में)

राज्य	एन	पी	के	एन+पी+के
आसाम	10.56	4.77	4.20	19.53
त्रिपुरा	3.90	2.21	1.38	7.49
मणिपुर	2.61	1.70	0.30	4.61
मेघालय	1.82	1.14	0.35	3.31
नागालैण्ड	0.18	0.21	0.04	0.43
अरुणाचल प्रदेश	0.10	0.02	—	0.12
सिक्किम	0.49	0.35	0.09	0.93
मिजोरम	0.18	0.23	0.03	0.44
टी० बोर्ड (उ० पू०)	14.79	4.71	18.26	37.76
योग उत्तर पूर्व :	34.63	15.34	24.65	74.62
सम्पूर्ण भारत :	4904.57	2114.50	796.38	7815.45

श्री शिवचरण सिंह : मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से मेरे प्रश्न के भाग "ग" में यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने यह बताया कि टोटल जो इम्पोर्ट है 1913.42, क्या यह बतायेंगे कि टोटल इम्पोर्ट हमारे यहां 2504.00 है, यह बाकी का जो बचा हुआ है फर्टिलाइजर इम्पोर्ट होता है उसमें कौन-कौन सी एजेंसियां इंपोर्ट करती हैं ? दूसरा मेरा यह प्रश्न है कि मेरे प्रश्न के उत्तर में आपने यह बताया है कि पोटाश और फास्फेट का हम लोगों के देश में कमी की वजह से सैल्फ-सफीशैंट नहीं हो पायेंगे, तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि हमारे देश में रॉ-पोटाशियम फास्फेट कहां-कहां मिलता है और कितना उसका उपयोग कर रहे हैं और कितने हमारे पास डिपाजिट्स मौजूद हैं और उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं ?

SHRI CHINTA MOHAN : Sir, I have said that M.M.T.C., which is a branch of the Department of Commerce, is looking after all these imports. The Government has decanalised everything regarding phosphatic fertilizers. Now, anybody can import these into this country—the producer can import; the State Governments can import—and we have nothing to do with the imports of phosphatics. Coming to self-sufficiency, as I said, we need three important ingredients, nitrogen, phosphate and potash. As for nitrogen, that is a urea which needs gas, we don't have plenty of gas available today. The Government is also exploring the possibility of going to different countries for joint ventures and trying to import urea. Coming to phosphate and potash, we don't have these ores, except very little phosphate in India and we have to totally depend upon other countries for potash and that is why we are not reaching self-sufficiency.

SHRI VIREN J. SHAH : His question is whether raw potash and phosphate ores are available anywhere in India.

श्री शिवचरण सिंह : माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि हमारे यहां फास्फेट के स्रोत नहीं हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि राजस्थान में फास्फेट के, रॉ मटैरियल के भारी स्त्रोत हैं, लेकिन आप उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं, नंबर वन 1 दूसरे, हमारा जो नाइट्रोजन है; उसमें भी 9 परसेंट की कमी है । आपने बताया कि 19.42 का हम इम्पोर्ट करते हैं और टोटल इम्पोर्ट 2504.00 है । तो यह 2504.00 और 19.42 के बीच का जो बचा हुआ भाग है, वह एम. एम. टी. सी. के अलावा किन-किन एजेंसियों ने इम्पोर्ट किया है, यह आप बताएं ।

SHRI CHINTA MOHAN : Every deposit will be examined and we will see the chemical composition. The chemical composition of the pyrites deposits in Rajasthan is not that good to go in for an industry there. The P.P.C.L. a public sector company under Fertilizer Department, is looking after that. They may start a factory in Rajasthan. As far as the second thing is concerned, apart from the M.M.T.C., nowadays, people are directly importing. There is a consortium of companies, private companies and public sector companies joined together, and they have imported certain raw materials recently. We have nothing to do with that. They can directly do it.

MR. CHAIRMAN : Mr. Singh, I think you have finished your second question.

श्री शिवचरण सिंह : महोदय, मेरे प्रश्न का तात्पर्य यह था कि प्राइवेट कम्पनीज जो इम्पोर्ट कर रही हैं, उनके इम्पोर्ट करने की कोई नीति है ?

MR. CHAIRMAN : You have finished. May I call Dr. Abrar Ahmed?

DR. ABRAR AHMED : Thank you, Mr. Chairman.

महोदय, उर्वरक का मसला एक राष्ट्रीय मुद्दा है । तो सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने किसान के उत्पादन के न्यूनतम मूल्य को इतना बढ़ाया जिससे कि वह आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ रहा है... (व्यवधान)... चेयरमैन सर, सच्ची और अच्छी बात सुनने की ये आदि नहीं हैं । मैं जिस चीज के लिए प्रधान मंत्री जी को बधाई दे रहा हूं, वह यह है कि उन्होंने किसान का उत्पादन मूल्य इतना बढ़ाया जितना कि आज तक नहीं बढ़ा था और इससे किसान आत्म-निर्भरता और स्वावलंबन की ओर बढ़ रहा है ।

MR. CHAIRMAN : Please hear him. (*Interruptions*)...

I think you are not hearing him. (*Interruptions*)...

डा. अबरार अहमद : माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने...

MR. CHAIRMAN : You please ask your question.

डा. अबरार अहमद : 662 करोड़ रुपये की ऐसी योजना किसानों के लिए दी है जिससे किसानों का उत्पादन किया हुआ सामान उचित मूल्य पर बिक सकेगा महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि पोटाश और फास्फोरस विदेश से आयात किया जाता है, उस पोटाश और फास्फोरस की क्या कोई वैकल्पिक वस्तु हमारे देश में बनाने के लिए शोध कार्य किया जा रहा है...

MR. CHAIRMAN : I think the answer has already been given to this. Has the Minister got anything more?

डा. अबरार अहमद : क्योंकि अधिकतम पोटाश और फास्फोरस विदेश से आयात करना पड़ता है । तो क्या उसके लिए कोई शोध कार्य किया जा रहा है जिससे वैकल्पिक उपयोग की वस्तु बनायी जा सके ?

MR. CHAIRMAN : I think the answer has already been given to this by the Prime Minister and the Minister. Mr. Gopalsamy.

SHRI V. GOPALSAMY : The hon. Minister in his statement mentioned that out of the total production, Urea alone constitutes 7340 MT. In the South the farmers use Di-ammonium Phosphate. In the North the manner of cultivation differs from the South. They use Urea. So the worst affected farmers are from the Southern States. If you go through the requirement schedule, it is the Southern States that have demanded more Di-ammonium Phosphate. Therefore, the price rise of Di-ammonium Phosphate has terribly affected the interest of the farmers. I would like to know whether the Government will take any steps.

MR. CHAIRMAN : Question Hour is over.